हरिभूमि
मध्यांचल भूमि
रायपुर, बुधवार 3 जून 2026

तापमान
अधिकतम 39.0 डिग्री
न्यूनतम 29.0 डिग्री

12 जनदर्शन में कलेक्टर से मिले चेंबर ऑफ ...

11 अंतर्राष्ट्रीय रैपिड शतरंज प्रतियोगिता में निष्ठा ने...

जर्जर पुल बना हादसे का कारण, एक और बाइक सवार दुर्घटना का शिकार

हरिभूमि न्यूज ⏭ हिरमी रावन

संडी-मोहरा होते हुए तिल्दा को जोड़ने वाले प्रमुख सड़क मार्ग पर स्थित भालूकोना और मोहरा के बीच की जर्जर पुलिया एक बार फिर दुर्घटना का कारण बन गई। ग्रामीणों के अनुसार इस पुल पर एप्रोच रोड का अभाव और पर्याप्त चेतावनी संकेत नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

मौके पर पहुंची टीम ने घायल व्यक्ति को प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उपचार के लिए अस्पताल भेजा। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया की जर्जर स्थिति और एप्रोच रोड की कमी के कारण अनजान वाहन चालक अक्सर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लोगों ने संबंधित विभाग से पुल का शीघ्र सुधार कराने, सुरक्षा संकेतक लगाने तथा एप्रोच रोड का निर्माण कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुलिया के कारण अब तक दर्जनभर से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

पुलिया पर फिर हादसा

दर्जनभर मौतों के बाद भी नहीं सुधरे हालात

सोमवार तड़के एक और दुर्घटना में बाइक सवार पुलिया के डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार पुल के नीचे जा गिरा, जबकि उसकी मोटरसाइकिल सड़क पर ही क्षतिग्रस्त अवस्था में बिखर गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल की मदद की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी।

खबर संक्षेप

क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे, कई घायल को कुछ गंवा रहे जाान

गोपालपुर। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार देर शाम सरसींवां थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार बुजुर्ग समेत दो लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार पचपेड़ी निवासी पिता लाल पटेल 60 वर्ष धौराभाटा से सब्जी बेचकर साइकिल से पचपेड़ी लौट रहे थे। इसी दौरान एक बाइक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर परिजन उन्हें सरसींवां स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक जमगहन चुरेला निवासी खेमलाल साहू भी घायल हो गया। उसकी आंख के ऊपर चोट लगने और रक्तचाप बढ़ने के कारण डॉक्टरों ने उसे भी बेहतर उपचार के लिए रेफर किया है। फिलहाल यह मामला पुलिस जांच का विषय है।

वन विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन की तैयारी

गिधौरी। बिलाईगढ़ विधानसभा के अंतर्गत वनांचल के नाम से प्रसिद्ध, सोनाखान तहसील के वन परिक्षेत्र बार नवापारा, कोठारी, देवपुर, अर्जुनी, सोनाखान आदि कई क्षेत्र में जंगली जानवरों का भयंकर खौफ विद्यमान है। आम जन दहशत में है। सुबह शाम घर से निकलना दूभर होते जा रहा है, फिर भी वन विभाग कोई स्थाई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिससे आम जन में नाराजगी व्याप्त है,ब्लॉक कांग्रेस कमेठी, सोनाखान अध्यक्ष युधिष्ठिर नायक ने मीडिया को बताया कि, हमारे भोले भाले आम जन, आये दिन जंगली जानवरों के शिकार हो रहे हैं और मौत के मुंह में जा रहे हैं। पिछले दिवस ग्राम दोन्द निवासी जरहू राम की हाथी के हमले से मौत हो गई।

गांजा तस्करी, महिला को सात साल कैद

रायपुर। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व गांजा बेचती गिरफ्तार महिला को विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस किरण थवाईत की कोर्ट ने सात साल कैद के साथ एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक भुवन लाल साहू के अनुसार कोर्ट ने कुकुर बेड़ा निवासी ज्योति देवार को कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने ज्योति को कुकुर बेड़ा स्थित डूमर तालाब बायपास रोड के पास थैले में रख कर गांजा बेचते गिरफ्तार किया था। महिला के कब्जे से पुलिस ने एक किलो 422 ग्राम गांजा जब्त की थी।

उड़नदस्ता दल करेगा थोक व फुटकर विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

मानसून से पहले हरकत में प्रशासन, खाद दुकान पर दबिश

हरिभूमि न्यूज ⏭ बलौदाबाजार

जिले में संचालित कृषि आदान विक्रय केंद्रों का सघन जांच अभियान जारी है तथा अनियमिता पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को उर्वरक निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 17 बॉटल नैनो यूरिया जब्त कर 2 सहकारी समिति एवं 2 कृषि सेवा केंद्रों को नोटिस जारी किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड पलारी के निरीक्षक सुचिन वर्मा ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, रोहांसी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहकारी समिति में संधारित ह्युमिक एसिड से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न करा पाने के कारण उपलब्ध 17 बोतल 500 एमएल ह्युमिक एसिड जब्त कर समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, छेरकापुर का निरीक्षण के दौरान सहकारी समिति में भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरक स्कंध एवं पॉस मशीन में प्रदर्शित मात्रा में भिन्नता पाए जाने के कारण समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
ग्राम देवसुन्द्रा में ⏭ शेष पेज 11 पर

उर्वरक भण्डारण वितरण का कार्य निरंतर जारी

इस वर्ष समितियों में यूरिया, डीएपी एवं पोटाश के अतिरिक्त एनपीके, एसएसपी, नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का भी पर्याप्त मात्रा में भंडारण किया गया है। जिले को यूरिया 42930, डीएपी 16500, पोटाश 3500, एसएसपी 8000 तथा एनपीके 14500 कुल 85430 मे.टन का उर्वरक लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके विरुद्ध उर्वरक भण्डारण यूरिया 19414, डीएपी 4315, पोटाश 2062, एसएसपी 4896 तथा एनपीके 5113 कुल 35800 मे.टन हो चुका है, तथा वितरण यूरिया 6348, डीएपी 18641, पोटाश 618, एसएसपी 1258 तथा एनपीके 2128 कुल 12216 मे.टन किया जा चुका है। केवल सहकारी समितियों में अद्यतन 25976 में टन उर्वरक का भण्डारण किया जा चुका है। जिले में उर्वरक भण्डारण वितरण का कार्य निरंतर जारी है।

जिले के 39 नवीन सहकारी समिति को मिली पीओएस मशीन : खाद वितरण शुरू

बलौदाबाजार। ग्रामीण सेवा सहकारी समितियों के पुनगर्ठन योजना अंर्तगत जिले में 39 नवीन ग्रामीण सेवा सहकारी समिति का गठन किया गया है। सभी नवीन 39 सहकारी समितियो को खाद के सुगमतापूर्ण वितरण हेतु पीओएस मशीन प्रदाय की गई। पीओएस मशीन उपलब्ध होते ही सभी नवीन समितियों में किसानों को सुगम खाद-बीज का वितरण किया जा रहा है। नवीन गठित 39 सहकारी समितियों के 89 पंचायतों में 112 ग्रामों के 43639 किसानों को इससे लाभ हुआ है। किसानों को खेती किसानी के लिये सुगमता पूर्वक त्वरित एवं अपने गृह ग्राम के निकट ही खाद बीज एवं नगद ऋण प्राप्त हो रहा है,जिससे किसानों में खुशी व्याप्त है। 39 नवीन समितियों में अभी तक 112 ग्रामों के 43639 किसानों को खाद प्रदाय हेतु 1876 टन का खाद का भंडारण एवं 353 टन खाद का वितरण के साथ कुल 48 करोड़ 99 लाख का ऋण वितरण किसानों को किया जा चुका है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार खरीफ सीजन में जिले के किसानों को आवश्यकता अनुसार सहकारी समितियों से खाद बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कृषि केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध हो सके।

गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल गठित

बलौदाबाजार। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में खरीफ वर्ष 2026 हेतु उर्वरक एवं बीज का भण्डारण, वितरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। उड़नदस्ता दल में नोडल अधिकारी सहायक संचालक कृषि नारद कुमार भारद्वाज, सदस्य सहकारिता निरीक्षक देवेन्द्र नेताम, पर्यवेक्षक तेजनाथ साहू, प्रोग्रामर नरेन्द्र वर्मा, वाहन चालक कुमार भारद्वाज, भृत्य शंकर लाल साहू शामिल है।उड़नदस्ता दल द्वारा सहकारी एवं निजी उर्वरक एवं बीज विक्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया जाएगा एवं अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। कृषकों को रसायनिक उर्वरकों की अधिक दर पर विक्रय तथा कालाबाजारी, जमाखोरी व प्रवर्तन के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे। उर्वरक विक्रय केन्द्रों में रसायनिक उर्वरकों के भौतिक स्कंध एवं पॉस मशीन में उपलब्ध स्कंध का मिलान करते हुए भिन्नता पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। जिले में स्थित भाटापारा रेक पाईंट से जिले को आबंटित उर्वरकों की प्रदाय मात्रा अनुसार प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे साथ डबल लॉक में भण्डारित उर्वरकों का सहकारी समितियों में आवश्यकतानुसार भण्डारण एवं कृषकों को वितरण की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही अनुदान प्राप्त उर्वरक का गैर कृषि कार्य यथा पशु आहार निर्माण, रेसिन एवं प्लाईवुड उद्योग में उपयोगिता के संबंध में उद्योग विभाग से सूची प्राप्त कर निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। कृषकों को वैकल्पिक, संतुलित उर्वरक एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित उर्वरक समूह क्रय कर उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे।

खंडहर में तब्दील हुआ अर्जुनी का निरीक्षण कुटी केंद्र

हरिभूमि न्यूज ⏭ अर्जुनी

विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम अर्जुनी में इंदिरा कॉलोनी एवं मेन रोड में स्थित निरीक्षण कुटी खंडहर में तब्दील हो चुका है। व्यवस्थित व्यवस्थाओं की मिसाल माना जाने वाला गेस्ट हाउस आज बदहाली, उपेक्षा और प्रशासनिक लापरवाही का जीवंत उदाहरण बन चुका है। एक समय निरीक्षण केंद्र भवन अंचल की प्रतिष्ठा, मेहमाननवाजी और सुव्यवस्थित प्रबंधन की पहचान हुआ करता था, लेकिन अब इसकी हालत देखकर ऐसा प्रतीत होता है। मानो वर्षों से इसे जानबूझकर बर्बादी के हवाले छोड़ दिया गया हो। कभी बाहर से आने वाले उच्च अधिकारियों, अतिथियों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होने वाले मेहमानों के स्वागत का प्रमुख केंद्र रहा जिसे गेस्ट हाउस के नाम से पहचान मिला वह अब खंडहर में तब्दील होता
⏭ शेष पेज 11 पर

क्षेत्र में पहले से ही गेस्ट हाउस की भारी कमी

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस अर्जुनी क्षेत्र में पहले से ही गेस्ट हाउस की भारी कमी है, वहां मौजूद इस महत्वपूर्ण भवन को आखिर क्यों बर्बाद होने दिया गया? जब बाहर से अधिकारी पहुंचते हैं तो उनके ठहरने की समुचित व्यवस्था तक नहीं हो पाती, इसके बावजूद प्रबंधन की निष्क्रियता समझ से परे दिखाई देती है। कर्मचारियों करोड़ों की संपत्ति बदहाली की शिकार, जर्जर दीवारें और टूटी व्यवस्थाएं खोल रहीं सिस्टम की पोल ।

टोनाटार में निर्विरोध पंच बने कोमलकांत

अर्जुनी। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 में भाटापारा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत टोनाटार में आपसी सहमति और निर्विरोध निर्वाचन की तस्वीर देखने को मिली। जहां वार्ड 13 में पंच पद के लिए हुए उपचुनाव में युवा समाजसेवी कोमलकांत यादव निर्विरोध पंच चुने गए। विदित हो कि ग्राम पंचायत टोनाटार में वार्ड 13 के पंच ओमेशकांत यादव के निधन के बाद पंच पद के लिए रिक्त हुए स्थान पर 1 जून को उपचुनाव हुआ। इसमें मृतक पंच के बड़े भाई कोमलकांत यादव को वार्डवासियों ने निर्विरोध पंच चुना। निर्विरोध पंच चुने जाने के बाद कोमलकांत यादव को सरपंच एवं सरपंच संघ उपाध्यक्ष विष्णु कोसले, उपसरपंच कुलेश्वर पिंकू, पंच राहुल घृतलहरें, रूपनारायण, डिगेश सहित पंचायत पदाधिकारियो ने बधाई दी है।

अनियंत्रित ट्रक दुकान में घुसा, बड़ी दुर्घटना टली

हरिभूमि न्यूज ⏭ सिमगा

नगर में सोमवार की सुबह 6 बजे नगर के हृदय स्थल जय स्तंभ चौक में एक दस चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सांकेतिक बोर्ड को क्षतिग्रस्त करते हुए दुकान के समीप नाली में जा घुसा। उक्त घटना में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई क्योंकि दुर्घटना के समय चौक खाली था, लेकिन यही दुर्घटना 8 या 9 बजे के आसपास होती तो गंभीर घटना घट सकती थी।

विदित हो कि, जय स्तंभ चौक नगर का हृदय स्थल है। यहां हमेशा लोगों की भीड़ रहतीं हैं, जिस स्थान पर ट्रक घुसा है उसी स्थान पर फल ठेला सब्जी आदि के व्यवसाय करने वाले लोग एवं ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। नगर के अन्दर भारी वाहनों के लगातार दौड़ने से पूर्व में भी अनेक दुर्घटनाएं घट चुकी है, जिसमें कई लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। बताते चले कि कुछ वर्ष पूर्व पुराने बस स्टैंड के समीप एक दस चक्का ट्रक का ब्रेक फेल होने के चलते तीन युवक एवं 9 मवेशियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। इस कारण शासन प्रशासन को आम लोगों के भारी रोष का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी घटना में मोबाइल दुकान के अंदर ट्रक जा घुसी थी, जिससे दुकान संचालक की मौत हो गई थी।तीसरी घटना में राजधानी पान दुकान में भी एक ट्रक जा घुसा था।
⏭ शेष पेज 11 पर

शासन की रियायतों का दिखने लगा असर

महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में बढ़ोतरी

हरिभूमि न्यूज ⏭ बलौदाबाजार

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के नाम पर होने वाले संपत्ति पंजीयन में पंजीयन शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट तथा 12 प्रतिशत उपकर को समाप्त किए जाने का सकारात्मक प्रभाव अब जिले में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। शासन की इन रियायतों के चलते महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीद और पंजीयन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जो कि ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अधिक देखी गई है।

जिला पंजीयक कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में जिले के पांचों उप पंजीयक कार्यालयों में महिलाओं के पक्ष में कुल 319 दस्तावेज पंजीकृत हुए थे। अप्रैल 2026 में यह संख्या 309 रही छूट मिलने के बाद मई 2026 में बढ़कर 445 पहुंच गई। केवल बलौदाबाजार उप पंजीयक कार्यालय में मई 2025 में महिलाओं के नाम 72 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था, जो अप्रैल 2026 में 78 और मई 2026 में बढ़कर 119 हो गया।

इसी प्रकार पलारी में मई 2025 के 43 दस्तावेज बढ़कर मई 2026 में 56, सिमगा में 84 से बढ़कर 99, कसडोल में 45 से बढ़कर 50 तथा भाटापारा में 75 से बढ़कर 121 दस्तावेज हो गए। यह वृद्धि दर्शाती है कि महिलाओं को दी गई पंजीयन शुल्क छूट का लाभ बड़ी संख्या में परिवार उठा रहे हैं। शहरी क्षेत्र बलौदाबाजार और भाटापारा के आंकड़ों में अधिक वृद्धि देखी गई है।

जिला पंजीयक विनोज कोचे ने बताया कि राज्य शासन की इस पहल का सीधा लाभ महिलाओं को मिल रहा है। संपत्ति खरीदने की लागत कम होने से
⏭ शेष पेज 11 पर

107 अधिक दस्तावेजों का पंजीयन दर्ज किया गया

बलौदाबाजार उप पंजीयक विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि अप्रैल 2026 से 12 प्रतिशत उपकर को समाप्त किए जाने के बाद पंजीयन में और तेजी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक केवल बलौदाबाजार उप पंजीयक कार्यालय में 107 अधिक दस्तावेजों का पंजीयन दर्ज किया गया है। इससे आम नागरिकों को राहत मिलने के साथ शासन के राजस्व में भी वृद्धि हो रही है।

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस निर्णय से महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। पंजीयन विभाग को उम्मीद है कि आने वाले समय में महिलाओं के पक्ष में संपत्ति पंजीयन के मामलों में और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी।

रोड से समीप दुकान लगाने वाले को नोटिस दी

इस संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी शशिभूषण श्रीवास्तव ने कहा कि सड़क किनारे लगे बोर्ड होर्डिंग आदि को हटवाने के लिए नोटिस देने एक अभियान चलाया जाएगा, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। उन्होंने कहा कि नगरपालिका द्वारा रोड से समीप दुकान लगाने वाले को नोटिस दी गई है। बुधवार से पुलिस टीम के साथ सयुंक्त टीम बना कर कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री कश्यप ने कहा- वन विभाग की विभागीय जांच 3 माह में निपटाएं, देर पर नपेंगे अफसर

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

वन मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग में वर्षों से लंबित विभागीय जांच प्रकरणों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए आगामी तीन माह के भीतर सभी पुराने मामलों का अनिवार्य रूप से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

- वर्षों से लंबित मामलों की होगी समीक्षा, जवाबदेह तय होंगे अधिकारी

उन्होंने कहा, निर्धारित अवधि के बाद यदि पुराने प्रकरण असामान्य अथवा अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किए जाते हैं, तो संबंधित जांचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। वन मंत्री ने कहा, विभागीय जांच मामलों में अनावश्यक देरी प्रशासनिक कार्यप्रणाली को कमजोर करती है और कर्मचारियों को वर्षों तक मानसिक, सामाजिक तथा सेवा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शासन व्यवस्था में निर्णयहीनता और अनावश्यक विलंब के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, अनेक मामलों में विभागीय जांच प्रस्ताव 4 से 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि कुछ प्रकरण संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद भेजे जाते हैं। यह स्थिति सुशासन, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन की भावना के विपरीत है।

न्याय में विलंब, न्याय से वंचित करने के समान

उन्होंने कहा, लंबे समय तक प्रकरण लंबित रहने से अभिलेखों और साक्ष्यों के परीक्षण में कठिनाई आती है तथा विभागीय कार्यवाही की गंभीरता और प्रभावशीलता भी प्रभावित होती है। कई कर्मचारी वर्षों तक बिना किसी निर्णय के अनिश्चितता की स्थिति में कार्य करने को विवश रहते हैं, जिससे उनके सेवा हित, पदोन्नति, पेंशन और व्यक्तिगत जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, यदि कोई कर्मचारी दोषी है तो उसके विरुद्ध समय पर कार्रवाई होनी चाहिए और यदि वह निर्दोष है तो उसे अनावश्यक उत्पीड़न एवं अनिश्चितता से शीघ्र राहत मिलनी चाहिए। न्याय में विलंब, न्याय से वंचित करने के समान है।

एक माह में सभी प्रकरण की जानकारी जुटाएं

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि एक माह के भीतर विभाग में पूर्व से लंबित सभी विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी संकलित की जाए तथा सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा, जवाबदेही तय किए बिना प्रशासनिक सुधार संभव नहीं है। विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, समयबद्ध निर्णय और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सुशासन की मूल आवश्यकता है। उन्होंने कहा, शासन का उद्देश्य केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें कर्मचारियों को समय पर न्याय मिले, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हो और जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय हो।

खबर संक्षेप

बीएसयूपी कॉलोनी में मन की बात का किया सामूहिक श्रवण

रायपुर। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा शहर जिला रायपुर द्वारा भक्त माता कर्मा वार्ड क्रमांक-67 स्थित बीएसयूपी कॉलोनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा देश के विकास जनभागीदारी, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े प्रेरणादायी विचारों को सुना गया। उपस्थितजनों ने राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में विधायक सुनील सोनी, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव कुमार अग्रवाल, छग फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन, पूर्व प्रदेश मंत्री किशोर महानंद, प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष बसंत बाघ, अजा. मोर्चा रायपुर जिला के अध्यक्ष पंकज जगत, जिला कार्यक्रम प्रभारी सोनूचंद बघेल, कार्यक्रम संयोजक देवराज महानंद, खेमलाल कोशले, पार्षद सोनू तिवारी, पार्षद रवि सोनकर, पार्षद कुबेर सपहा सहित मोर्चा के पदाधिकारी एवं वार्डवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

पुलिस कमिश्नर ने स्वास्थ्य शिविर का किया निरीक्षण

रायपुर। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई एवं रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एमएमआई हॉस्पिटल में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर पिछले दस दिन से चल रहा है। इस दौरान पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने एमएमआई हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी आंखों का एवं रुटीन चेकअप कराया। सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने बताया, दस दिन से शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पुलिस कमिश्नरेट के 300 से ज्यादा लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। इस अवसर पर एसीपी तारकेश्वर पटेल के अलावा सिंधी काउंसिल के महामंत्री सुनील कुकरेजा, विक्की लोहाना, युवा विंग अध्यक्ष जीतू लोहाना, रितेश वाधवा, धनेश मटलानी, रोशन ओछवानी, हरीश मांगतानी, लक्ष्मी बजाज चंचलानी आदि उपस्थित थे।

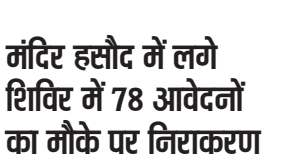

मंदिर हसौद में लगे शिविर में 78 आवेदनों का मौके पर निराकरण

रायपुर। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत आरंग विकासखण्ड के नगर पालिका परिषद मंदिर हसौद में सोमवार को जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आवेदन लेकर पहुंचे थे। इस दौरान 78 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। इनमें मुख्य रूप से राशन कार्ड, आधार कार्ड, श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित विभिन्न दस्तावेजों से जुड़े प्रकरण शामिल रहे। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया। इस दौरान मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम कार्ड एवं उनके नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 14 हितग्राही, कृषि विभाग ने 3 किसानों को खाद बीज वितरण किया।

यूडीआईडी कार्ड नहीं बनने से दिव्यांजनों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा

प्रदेश में पंजीकृत 7.50 लाख दिव्यांग, इनमें अब तक 2.50 लाख के ही बन पाए हैं यूडीआईडी कार्ड

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

दिव्यांगजनों को अब विशिष्ट दिव्यांगता (यूडीआईडी) कार्ड बनाना अनिवार्य है। इस कार्ड के आधार पर ही दिव्यांगजनों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना है, लेकिन प्रदेश में यूडीआईडी कार्ड बनाने का कार्य इतना धीमा चल रहा है कि पंजीकृत लगभग साढ़े 7 लाख में ढाई लाख के करीब दिव्यांगजनों के ही यूडीआईडी कार्ड बन पाए हैं, जबकि 5 लाख कार्ड बनाए जाने बाकी हैं। इधर दिव्यांजन संघ के प्रदेश अध्यक्ष डोमान बया का कहना है कि यूडीआईडी कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग की है। इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाने चाहिए, ताकि जल्द से जल्द लोगों के यूडीआईडी कार्ड बन सके।

केंद्र सरकार ने श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड की तरह दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना का लाभ लेने के लिए यूडीआईडी कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया है। यह कार्ड समाज कल्याण विभाग या मान्यता प्राप्त सीएससी केंद्र में बनने हैं। इसके लिए दिव्यांगजन को आवेदन करना है। इस आवेदन में दिव्यांगजन का पंजीकृत नंबर एवं आधार नंबर देना अनिवार्य है। अगर पंजीकृत नहीं है, तो उसे पहले अपना पंजीयन करना होगा। विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार प्रदेशभर में पंजीकृत दिव्यांगजनों की संख्या लगभग साढ़े 7 लाख है, जिनमें से अब तक लगभग ढाई लाख दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड बनाए गए हैं। शेष दिव्यांगजनों के अब तक यूडीआईडी कार्ड बन नहीं पाए हैं।

शिविर नहीं लगाए जाने से नहीं बन पा रहे

शिविर नहीं लगाए जाने से यूडीआईडी कार्ड बन नहीं पा रहे हैं, जिससे दिव्यांगजनों को योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। पूर्व में दिव्यांगजनों के लिए जो सर्वे हुआ है, उसमें खानापूर्ति की गई है। घर-घर सर्वे के लिए टीम पहुंची ही नहीं है।
- **डोमन बया,** अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन संघ

अब तक ढाई लाख बन चुके

दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड बनाना अनिवार्य है। प्रदेशभर में अब तक लगभग ढाई लाख के बन चुके हैं, वहीं शेष दिव्यांगजनों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है। समाज कल्याण विभाग, चॉइस सेंटर में आसानी से बन रहे हैं। छूटे हितग्राहियों के जल्द से जल्द कार्ड बन जाए, इसके लिए सभी जिलों में विशेष शिविर लगाए जाने के निर्देश दिए हैं।
- **लोकेश कावड़िया, अध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम

सूची की जांच हुई तो मृतकों के साथ दूसरे जिलों के नाम भी मिलेंगे

प्रदेश में पंजीकृत दिव्यांगजनों की सर्वे के बाद जो सूची तैयार की गई थी। इसमें कई नाम ऐसे भी सामने आ सकते हैं, जिनकी मृत्यु चुकी हैं, या फिर वे दूसरे जिले के निवासी हैं। सूत्रों के अनुसार जिन दिव्यांजनों के यूडीआईडी कार्ड नहीं बने हैं, उनमें ऐसे दिव्यांगजनों के नाम भी शामिल होने की संभावना हैं।

सर्वे कागजों में, पुरानी सूची के आधार पर रिपोर्ट तैयार

तत्कालीन कांग्रेस के शासनकाल में पूरे प्रदेश में नए दिव्यांजनों का पता लगाने और डॉटा अपडेट करने के लिए कई सालों के बाद एजेंसी के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सभी जिलों में पंजीकृत दिव्यांगजनों का डॉटा अपडेट हुआ था। हालांकि सूत्रों की मानें तो यह सर्वे कागजों में ज्यादा एवं धरातल पर कम हुआ था। राजधानी रायपुर में ही लगभग 10 से 20 प्रतिशत घरों में घुमकर सर्वे की लिस्ट तैयार कर ली गई थी। यहीं कारण है कि उस समय कई वार्डों के पाषर्दों को ही इस सर्वे की जानकारी तक नहीं थी।

कार्ड नहीं बनने से योजनाओं से वंचित

दिव्यांगजन के लिए यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य सितंबर 2024 से देश में लागू है। इस तरह इसे लागू हुए डेढ़ वर्ष से अधिक समय बीता चुका है। इसके बाद भी प्रदेश में लाखों दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड बन नहीं पाए हैं। कार्ड नहीं बनने से दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी, आरक्षण, छात्रवृत्ति, जैसे अन्य कई लाभ भी नहीं मिल पा रहे।

विधिक शिविर में दी साइबर अपराध रोकने की जानकारी

हरिभूमि न्यूज ⏭ भटगांव

तालुका विधिक सेवा समिति भटगांव के अध्यक्ष न्यायाधीश पुनीतराम गुरुपंच के नेतृत्व में शनिवार को ग्राम गिरवानी, घाना व गधाभाठा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मोटर यान अधिनियम, पीड़ित क्षतिपूर्ति, सट्टा एवं जुआ प्रतिषेध अधिनियम, आबकारी एक्ट, घरेलू हिंसा के सम्बन्ध में जानकारी तथा नालसा द्वारा 'तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015 मुख्य रूप से उन लोगों की सहायता के लिए बनाई गई है जो मानव तस्करी और यौन शोषण का शिकार हुए ऐसे नियमों की जानकारी दी गई। इस योजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य विधिक सहायता तथा न्याय तस्करी के शिकार लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह और वकील उपलब्ध कराना ताकि वे अपनी गरिमा और कानूनी अधिकारों की रक्षा कर सकें। समाज के कमजोर वर्गों को तस्करी के खतरों के प्रति जागरूक करना और उन्हें शोषण से बचाने के लिए कदम उठाना।

इसके अतिरिक्त विधिक साक्षरता शिविर में साइबर अपराध के बारे में जानकारी प्रदान की गई, जिसमें साइबर अपराध के बारे में विस्तार से बताया गया। उक्त विधिक साक्षरता शिविर में ग्रामवासी एवं आमजन उपस्थित थे, जिसमें सहयोगी व्यवस्थापक के रूप में पुलिस थाना भटगांव के आरक्षक परवेश खटकर, पैनल अधिवक्ता डगेश खटकर, नरेश एवं कामदेव द्वारा अपनी सेवा विशेष सहयोग कर प्रदान की गई।

धान खरीदी के लिए खुलेंगे नए 320 केंद्र

मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में खरीफ की तैयारियों पर चर्चा

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2026-27 में धान खरीदी के लिए राज्यभर में 320 नए केंद्र खोलने की तैयारी है। राज्य में अब तक 2740 केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की जाती रही है। नए खरीद केंद्र खुलने से किसानों को अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचने में आसानी होगी। राज्य में नए खरीफ सीजन 2026-27 की तैयारियों के सिलसिले में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक भी हुई है।

- खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक भी हुई

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रि मण्डलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति के सदस्यगण कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिक मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। उप मंत्रिमण्डलीय समिति के बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के निष्पादन एवं कस्टम मिलिंग तथा आगामी खरीफ सीजन में धान खरीदी के तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, वित्त विभाग के सचिव रोहित यादव, सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना, मार्कफेड के एमडी जितेन्द्र शुक्ला, मंडी बोर्ड के एमडी महेन्द्र सिंह सवन्नी सहित अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

खरोरा की 14 समितियों में 75 प्रतिशत खाद्य का भंडारण

हरिभूमि न्यूज ⏭ खरोरा

खरीफ सीजन 2026 को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए नई खाद वितरण नीति लागू की है। नई व्यवस्था के तहत यूरिया और डीएपी (DAP) खाद का वितरण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा तथा नैनो एवं जैविक उर्वरकों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जिसमें खरोरा शाखा जिला सरकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत 14 समितियों में पर्याप्त मात्रा में 75% खाद का भंडारण विभिन्न सरकारी समितियों में किया जा चुका है।

जिसमें खाद का कुल भंडारण 2918.19 टन तथा विभिन्न 14 समितियों में किसानों को 890.715 टन का वितरण किया जा चुका है जो लगभग 30 प्रतिशत है। इसमें किसानों को खाद वितरण हेतु 2027.475 टन वितरण करना अभी शेष है। जिसमें सरकारी समिति बेलदार सिवनी में खाद भंडारण 123.800 टन किसानों को खाद वितरण 26 टन, बूढ़ेडा सरकारी समिति में भंडारण 167.509 वितरण 41 टन , इसी प्रकार कुम्हारी सरकारी समिति में भंडारण 265.800 टन वितरण 46 टन, बंगोली सरकारी समिति में भंडारण 129.700 टन एवं वितरण 22.00 टन, पचरी सरकारी समितियों में भंडारण 215.735 टन वितरण 43.00 टन , सहकारी समिति छड़िया में भंडारण 239.650 टन वितरण 46.00 टन, सहकारी समिति बूढ़ेनी वितरण 288.335 टन जिसमें वितरण 155.00 टन, सहकारी समिति फरहदा में भंडारण 319.570 टन वितरण 151.00 टन, खरोरा सहकारी समिति में भंडारण 221.685 टन वितरण 53.000, सरकारी समिति माठ में भंडारण 167.700 टन वितरण 35 टन, गनियारि सहकारी समिति में भंडारण 129.700 टन वितरण 54.715 टन, सरकारी समिति असोंदा में भंडारण 135.165 वितरण 41.00 तथा इसी प्रकार सहकारी समिति अडसेना में भंडारण 246.100 टन एवं वितरण 86.00 टन खाद वितरण किया गया है । उक्त जानकारी जिला सरकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित खरोरा के शाखा प्रबंधक भरत साहू ने देते हुए कहा कि किसानों के लिए खाद एवं बीज की मांग समय समय पर किया जा रहा है एवं शासन के आदेशानुसार किसानों को सभी समितियों में खाद एवं बीज का वितरण नियमानुसार किया जाएगा ।सरकार के निर्देशानुसार खरीफ 2025 में किसानों को जितना यूरिया मिला था, इस वर्ष उसकी 80 प्रतिशत मात्रा पारंपरिक यूरिया के रूप में दी जाएगी। शेष आवश्यकता उपलब्धता के अनुसार या नैनो यूरिया के माध्यम से पूरी की जाएगी।

नैनो यूरिया व नैनो डीएपी के उपयोग से शैलेन्द्र ने पकड़ी आधुनिक खेती की राह

बलौदाबाजार। पारंपरिक खेती को छोड़कर जब कोई किसान आधुनिकता का हाथ थामता है, तो वह न सिर्फ अपनी तकदीर बदलता है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन जाता है। ग्राम लटुवा के प्रगतिशील किसान शैलेंद्र कुमार कन्नौजे आज एक ऐसी ही मिसाल बनकर उभरे हैं। पिछले दो वर्षों से नैनो उर्वरक का लगातार उपयोग करके वे उन्नत और स्मार्ट खेती की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। उन्नत कृषि अपनाकर शैलेन्द्र को रासायनिक खादों के भारी-भरकम बोझ से मुक्ति मिली और कम लागत में अधिक मुनाफे की एक शानदार मिसाल पेश किया है। किसान शैलेंद्र कुमार बताते हैं कि, खेती में लगातार बढ़ती लागत और पारंपरिक बोरी वाले खादों के परिवहन व छिड़काव में आने वाली दिक्कतों ने उन्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर किया था। जब उन्होंने नैनो तकनीक को अपनाया, तो इसके परिणाम बेहद चौंकाने वाले और संतोषजनक रहे। यही वजह है कि अपनी इस सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने इस वर्ष भी अपनी फसलों में पूरी तरह से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का ही उपयोग करने का मन बनाया है। उनके अनुसार,

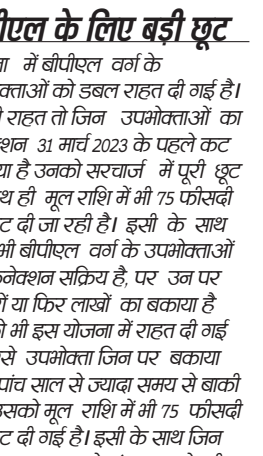

नैनो उर्वरक बाजार में बहुत ही कम लागत में और आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे खेती के शुरुआती खर्च में बड़ी बचत होती है। इस आधुनिक तकनीक का सबसे बड़ा व्यावहारिक फायदा इसके रखरखाव और उपयोग में देखने को मिलता है। जहां पहले भारी-भरकम बोरियों को दुकान से खेत तक लाने और फिर उनका छिड़काव करने में किसानों का पसीना छूट जाता था, वहीं अब आधे लीटर की छोटी बोतलें आसानी से कहीं भी ले जाई जा सकती हैं और पानी में घोलकर इनका खेतों में छिड़काव करना बेहद सरल हो गया है। इसके अलावा नैनो तकनीक के कारण पौधों को पोषक तत्व सीधे और सही मात्रा में मिलते हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों में बेहतरीन सुधार आया है। शैलेंद्र कुमार कन्नौजे की यह पहल आज पूरे जिले के किसानों को आधुनिक और आत्मनिर्भर खेती की एक नई राह दिखा रही है।

अंबिकापुर पहले, बिलासपुर दूसरे और रायपुर तीसरे नंबर पर

अब पांच फीसदी पंजीयन शुल्क में ही बिजली बिल बकाया का समाधान

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

प्रदेश के करीब नौ लाख उपभोक्ताओं के बकाया बिल का निराकरण करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री बिजली बिल बकाया भुगतान समाधान योजना चल रही है। इसमें अब तक करीब साढ़े सात लाख उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल का समाधान हो गया है। इसके लिए पहले दस फीसदी पंजीयन शुल्क जमा करना जरूरी रखा गया था, लेकिन अब इसको कम करके पांच फीसदी कर दिया गया है। ऐसा करने के पीछे का कारण यह है कि सभी उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया का समाधान हो सके।

पंजीयन शुल्क से ही छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी को 60 करोड़ मिल चुके हैं। योजना 30 जून तक चलेगी। प्रदेश में बिजली के आम उपभोक्ताओं पर ही तीन हजार करोड़ से ज्यादा का बकाया है। इसमें से 31 मार्च 2023 के पहले के उपभोक्ताओं पर डेढ़ हजार करोड़ से ज्यादा का बकाया है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए ही प्रदेश सरकार ने समाधान योजना का प्रारंभ किया है। इनका पूरा सरचार्ज माफ किया गया है। सरचार्ज की राशि ही 758 करोड़ है। इसमें से अब तक छह सौ करोड़ का सरचार्ज माफ हो चुका है।

अंबिकापुर नंबर वन

समाधान योजना का लाभ उठाने में अंबिकापुर पहले नंबर पर है। यहां के रीजन में 306171 उपभोक्ता बकायेदार हैं। इसमें ने पौने तीन लाख ने पंजीयन करा लिया है। इनसे पंजीयन के रूप में 21 करोड़ से ज्यादा मिले हैं। इसके बाद बिलासपुर का नंबर है। इस रीजन में 224635 उपभोक्ता बकायेदार हैं। इनमें से करीब पौने दो लाख ने पंजीयन कराया है। इनसे करीब 12 करोड़ मिले हैं। तीसरे नंबर पर रायपुर है। यहां पर एक लाख 17 हजार बकायेदार हैं। इनमें से एक लाख ने पंजीयन करा लिया है। इनसे 9 करोड़ मिले हैं। इसी तरह से अन्य रीजन में भी बकायेदारों ने पंजीयन कराया है। इसके लिए इनको बकाया राशि का दस फीसदी पंजीयन शुल्क के रूप में देना पड़ा है। लेकिन इसको पांच फीसदी कर दिया गया है।

कम किया पंजीयन शुल्क

सभी उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल का समाधान हो सके इसलिए अब पंजीयन शुल्क को दस फीसदी से कम करके पांच फीसदी कर दिया गया है।
- **भीम सिंह कंवर,** एमडी, वितरण कंपनी

एपीएल को दस फीसदी छूट

सामान्य वर्ग के उपभोक्ताओं को बकाया पर मूल राशि में दस फीसदी की छूट उस स्थिति में मिलेगी जब वे सारा बकाया एक साथ जमा करेंगे। अगर तीन किस्तों में बकाया किया जाएगा तो पांच फीसदी की छूट मिलेगी। छह किस्तों में बकाया जमा करने की भी सुविधा मिलेगी, लेकिन इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी।

बीपीएल के लिए बड़ी छूट

योजना में बीपीएल वर्ग के उपभोक्ताओं को डबल राहत दी गई है। पहली राहत तो जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन 31 मार्च 2023 के पहले कट हो गया है उनको सरचार्ज में पूरी छूट के साथ ही मूल राशि में भी 75 फीसदी की छूट दी जा रही है। इसी के साथ जिन भी बीपीएल वर्ग के उपभोक्ताओं का कनेक्शन सक्रिय है, पर उन पर हजारों या फिर लाखों का बकाया है उनको भी इस योजना में राहत दी गई है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर बकाया राशि पांच साल से ज्यादा समय से बाकी है, उसको मूल राशि में भी 75 फीसदी की छूट दी गई है। इसी के साथ जिन का बकाया एक से पांच साल के बीच है, उनको मूल राशि में 50 फीसदी छूट दी गई है।

खबर संक्षेप

ट्रांजिट मेस में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों का सम्मेलन

रायपुर। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग एवं जनसहभागिता को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुये सोमवार को पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का गरिमामय सम्मेलन पुलिस ट्रांजिट मेस में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने अपने उद्बोधन में कहा कि पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष विभाग एवं समाज की सेवा को समर्पित किए हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उनका अनुभव एवं सामाजिक समझ समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। सम्मेलन में सवा सौ से ज्यादा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी शामिल हुए।

वनबल प्रमुख से सौजन्य भेंट करने पहुंचे कर्मचारी

रायपुर। राज्य के नए पीसीसीएफ एवं वनबल प्रमुख अरुण कुमार पाण्डेय से सौजन्य भेंट करने छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत दुबे के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिला के कर्मचारी नए वनबल प्रमुख से सौजन्य मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। सौजन्य मुलाकात के दौरान कर्मचारियों ने वन संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और मैदानी कर्मचारियों के हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर नए वनबल प्रमुख ने कर्मचारियों को पूरी निष्ठा से काम करने के लिए प्रेरित किया । और उनकी जायज मांगों व समस्याओं के निराकरण के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया।

ढाबा संचालकों की पुलिस ने ली बैठक, दी हिदायत

रायपुर। ग्रामीण एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के निर्देशन में सोमवार को हाईवे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से ढाबा संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी उमाशंकर बांधे, एएसपी ग्रामीण अभिषेक झा तथा माना सीएसपी लंबोदर पटेल उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर संचालित ढाबों के संचालकों को शासन एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी प्रकार की शराब परोसना अथवा सेवन की अनुमति देना पूर्णतः अवैध है तथा ऐसे मामलों में संबंधित संचालक के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करने चेतावनी दी गई। ढाबा संचालकों को पुलिस ने आठ सुरक्षा मानक बिंदुओं का सख्ती से पालन करने निर्देश दिए हैं।

समय सीमा में काम नहीं हुआ या परेशानी आ रही तो कर सकेंगे 1076 में शिकायत

अधिकारियों को दिया गया 1076 सीएम हेल्पलाइन और सीएमएस का प्रशिक्षण

हरिभूमि न्यूज ⏭ बिलाईगढ़

फील्ड अधिकारी से लेकर सचिव को सीएम कंट्रोल रूम में देना होगा 1076 में आए आवेदन का जवाब

नागरिकों की सुविधा हेतु शिकायत दर्ज कराने के विभिन्न माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें 1076 हेल्पलाइन नंबर, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नागरिकों की और अधिक सुविधा हेतु सीएम हेल्पलाइन 1076 मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रशिक्षण में पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने, स्थिति जांचने, फीडबैक देने की प्रक्रिया, अधिकारियों को लॉगिन प्रक्रिया, प्रोफाइल अपडेट, डैशबोर्ड संचालन, लंबित शिकायतों की समीक्षा, समाधान विकल्प चयन एवं प्रतिवेदन (एटीआर) अपलोड के बारे में विस्तृत से बताया गया। फील्ड अधिकारी से सचिव को सीएम कंट्रोल रूम में 1076 में आए आवेदन का जवाब देना होगा। प्रशिक्षकों द्वारा सवालों, शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

सीएम हेल्पलाइन में नागरिकों के हक, पात्रता के बावजूद राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं हो रहा, उसे त्वरित रूप से निराकरण करने की मंशा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की है, जिसे आम आदमी तक पहुंचाने के लिए 1076 सीएम हेल्पलाइन प्रारम्भ की जा रही है। भविष्य में इसका शुभारम्भ के बाद कार्य प्रारम्भ होगा।

सीएम हेल्पलाइन में आवेदन पत्र देने के 4 माध्यम- सीएम हेल्पलाइन में आवेदन पत्र देने के 4 माध्यम है, इसमें 1076 डायल कॉल, पोर्टल, वाट्सअप पेज, मुख्यमंत्री विष्णु देव के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर शामिल है। इसमें जो आवेदन लिख नहीं पाते उनके लिए कॉल बैक करने का अनुरोध का भी विकल्प है, जिससे उनको कॉल बैक कर उनके आवेदन को दर्ज किया जाएगा।

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू की अध्यक्षता में सुशासन एवं अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियो का एवं ब्लॉक लेवल के अधिकारियों के लिए वीडियो कांफ्रेंस से सीएम हेल्पलाइन 1076 एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

यह प्रशिक्षण अनुराग दीवान के द्वारा दिया गया। उन्होंने जानकारी दी कि सीएम हेल्पलाइन त्वरित शिकायत निवारण हेतु एकीकृत मंच है तथा यह गुड गवर्नेंस की दिशा में राज्य शासन का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से नागरिकों की शिकायतों, सुझावों एवं समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन प्रणाली पाँच प्रमुख स्तंभों शिकायत ट्रैकिंग, समयबद्ध निवारण, नागरिक फीडबैक, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा कुशल निगरानी पर आधारित है। प्रत्येक दर्ज शिकायत को 12 अंकों का विशिष्ट टोकन क्रमांक प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता हर चरण में अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

प्रशिक्षकों द्वारा शिकायत श्रेणी (कंप्लेंट कैटेगरी) की अवधारणा को विस्तार से समझाया गया। प्रत्येक श्रेणी के लिए विभाग द्वारा एल-1 से एल-4 तक के अधिकारियों की पदनामवार मैपिंग की गई है। शिकायत निवारण हेतु निर्धारित समय-सीमा के अनुसार समय-सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायत का निराकरण नहीं होने पर शिकायत स्वतः अगले उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी।

कलेक्टर जनदर्शन में मिले 110 आवेदन अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश

बिलाईगढ़। कलेक्टर जनदर्शन में जिले के नागरिकों ने 110 आवेदन में सबसे ज्यादा मांग पीएम आवास के 11, पेंशन के 8, राशन के 7, शौचालय के 7 सहित सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू को अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियो को संबंधित मांग और शिकायत का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर जनदर्शन में बरमकेला ब्लॉक के ग्राम कर्राकोट की महिलाओ ने पेयजल सुविधा बोर बोरिंग की मांग की। इसी प्रकार 8 वर्ष से बेड में महिला मरीज का आधार कार्ड अपडेट के लिए आधार ऑपरेटर को घर भेजनें की मांग, भूमिहीन योजना, दुर्घटना के जीवन ज्योति बीमा और अन्य योजना, भू अर्जन, विद्युत कनेक्शन के लिए 10 विद्युत खम्भा, नक्शा बटानकन, कब्जा हटाने, ठगी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने, मारपीट गुंडागर्दी करने वालों पर कार्यवाही, खाद को ज्यादा रेट में बेचने की शिकायत, किसानों को फार्मर आईडी के आधार पर खाद बीज देने की मांग, केसीसी लोन दिलाने, निजी भूमि से ट्रांसफार्मर हटाने आदि की मांग की गई। पंच हटाने और सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक की शिकायत - बरमकेला ब्लॉक के ग्राम कर्राकोट की महिलाओ ने सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक की काम नहीं करने और मनमर्जी करने की शिकायत की है। इसी प्रकार मानिकपुर छोटे के वार्ड 9 के पंच को काम नहीं करने पर हटाने की शिकायत आया है।

- पीएम आवास के 11, पेंशन के 8, राशन कार्ड के 7 और शौचालय के 7 आवेदन

अंतर्राष्ट्रीय रैपिड शतरंज प्रतियोगिता में निष्ठा ने लहराया परचम

हरिभूमि न्यूज ⏭ खरोरा

सरगुजा जिले के अंबिकापुर में 31 मई से 1 जून तक आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रैपिड शतरंज प्रतियोगिता में खरोरा की प्रतिभाशाली छात्रा निष्ठा त्रिपाठी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अंडर-13 वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर नगर, विद्यालय एवं अपने माता-पिता का नाम गौरवान्वित किया है।

पीएम श्री भरत देवांगन शासकीय उत्कृष्ट हिन्दी-अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, खरोरा की छात्रा निष्ठा त्रिपाठी ने प्रतियोगिता के दौरान अपनी बौद्धिक क्षमता, रणनीतिक सोच, एकाग्रता तथा निरंतर अभ्यास का परिचय देते हुए शानदार खेल प्रदर्शन किया। देश-विदेश से आए प्रतिभागियों के मध्य प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल के दम पर प्रथम स्थान अर्जित किया।

निष्ठा की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार सहित पूरे खरोरा नगर में हर्ष का वातावरण है। उनकी सफलता यह दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन, निरंतर अभ्यास एवं कठिन परिश्रम के बल पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। शतरंज जैसे बौद्धिक खेल में उनकी यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी।

प्राचार्य रजनी मिंज ने कहा कि विद्यार्थियों की ऐसी उपलब्धियां विद्यालय के लिए गर्व का विषय हैं तथा इससे अन्य छात्र-छात्राओं को भी नई प्रेरणा मिलती है।

- खरोरा की प्रतिभाशाली छात्रा ने विद्यालय, नगर एवं परिवार का बढ़ाया गौरव
- अंडर-13 वर्ग में प्राप्त किया प्रथम स्थान

शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि निष्ठा ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर खरोरा नगर का मान बढ़ाया है। उनकी यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निष्ठा भविष्य में भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगी।

विद्यालय की वरिष्ठ व्याख्याता शाहिना परवीन ने भी निष्ठा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सफलता उनकी निरंतर मेहनत, आत्मविश्वास एवं समर्पण का परिणाम है। उन्होंने निष्ठा को भविष्य में और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने की शुभकामनाएं प्रदान कीं। निष्ठा की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर, नगर पंचायत उपाध्यक्ष सुमित सेन, सांसद प्रतिनिधि दुलेश साहू, यज्ञदत्त शर्मा, सुनील नायक, सचिन अग्रवाल, गुरदीप सिंह छाबड़ा, रश्मि वर्मा, गुरजीत कौर भाटिया, संजीव देवांगन, पंचराम यादव, योगेश द्विवेदी, सहित शिक्षक-शिक्षिकाओं, अभिभावकों एवं नगरवासियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। सभी ने निष्ठा त्रिपाठी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास जताया कि वह आगे भी अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर बड़ी सफलताएं अर्जित कर विद्यालय, नगर, प्रदेश एवं देश का नाम रोशन करती रहेंगी।

किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद - बीज वितरण सुनिश्चित कराएं विभाग

हरिभूमि न्यूज ⏭ बलौदाबाजार

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण कार्य एवं विभागीय कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने खरीफ सीजन में खेती के लिये सभी समितियों के माध्यम से किसानों को आवश्यकतानुसार गुणवत्ता युक्त खाद -बीज वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।

कलेक्टर शर्मा ने कहा कि 39 नये समिति गठित होने के साथ अब जिले में कुलदीप 168 सहकारी समिति संचालित हैं। सभी सहकारी समितियों में पीओएस मशीन उपलब्ध है, जिनके माध्यम से किसानों को खाद-बीज और ऋण वितरण कराएं। उन्होंने समितियों एवं कृषि केंद्रों में किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से खाद -बीज की उपलब्धता हेतु उडनदस्ता दल एवं राजस्व अधिकारियों के द्वारा सघन जांच जारी रखने तथा किसी भी केन्द्र पर अनियमितता पाए जाने पर सम्बंधित के खिलाफ कार्रवाई करने कहा। उन्होंने नैनो यूरिया एवं कीट नाशक के छिड़काव के लिये ड्रोन का उपयोग हेतु समूह की महिलाओ तथा चयनित सहकारी समिति के माध्यम से संचलित करने कहा। जिले में बीज उत्पादन के लिये बीज निगम एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों का पंजीयन एवं आवश्यक मशीनरी को सक्रिय करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने शिक्षा सत्र 2026-27 अंतर्गत आगामी 15 जून से शुरू हो रहे स्कूलों में पढ़ाई की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन स्कूलों में निर्माण कार्य अधूरे हैं उसे स्कूल खुलने से पहले पूरा कर लिया जाए। सभी स्कूलों में पेयजल, बिजली, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं कार्यशील हो। रंगाई -पोताई एवं साफ़ -सफाई भी दुरुस्त हो। स्कूल खुलने पर शिक्षकों की उपस्थित अटेंडेंस एप्प में हो। एसडीएम स्कूलों का औचक निरीक्षण करें। उन्होंने शाला प्रवेश उत्सव की तैयारी के भी निर्देश दिये।कलेक्टर ने आगामी शैक्षणिक सत्र में बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने के लिये अभी से रणनीति तैयार करने कहा। उन्होंने जिन स्कूलों का रिजल्ट 50 प्रतिशत से कम है उन स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षक की समीक्षा बैठक लेने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर सभी स्कूलों में हर माह टेस्ट लिया जाए।कमजोर प्रदर्शन वाले बच्चों के लिये रिमेडियल क्लास की व्यवस्था हो। हर माह स्कूलों की प्रगति रिपोर्ट लें।

इस दौरान लंबित राजस्व प्रकरण, सुशासन तिहार के आवेदन, स्वामित्व योजना, पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, पीएम आवास, मुख्यमंत्री जनदर्शन, सीपी ग्राम्स सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता, निशा नेताम मड़ावी सहित एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे ।

- विक्रय केंद्रों की सतत जांच और अनियमितता पर होगी कार्रवाई
- स्कूल खुलने के पूर्व अधूरे निर्माण पूर्ण कराने व बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश

गहरीकण के बाद तालाबों को नहर से जोड़ा जाएगा

भटगांव। नगर पंचायत भटगांव के किसान सभा के वर्षों पुरानी मांग पर अंडबंधा तालाब के गहरीकरण के साथ विभिन्न तालाबों को केनाल के माध्यम से जोड़ने की स्वीकृति नगर पंचायत भटगांव को प्राप्त हुई है।

उल्लेखनीय है कि किसान संघ भटगांव द्वारा लगातार मांग की जाती थी कि मुख्य सिंचाई हेतु निर्मित प्रबंध तालाब का गहरीकरण करना व किसानों के व्यापक हित को देखते हुए और अंडबंधा से बड़ा तालाब, झलवा तालाब, दर्री, दांतारा, बुधुबन गस्तिहा, लामी को जोड़ने हेतु केनाल बनाया जाए जिससे किसानों को सही समय पर कृषि कार्य हेतु सिंचाई जल की आपूर्ति की जा सके।

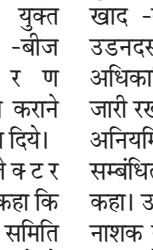

इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष विक्रम कुर्रे ने बताया कि किसान संघ के अथक प्रयास और मांग पर अंडबधा तालाब के गहरीकरण हेतु शासन से प्रशासकीय एवं वृत्त स्वीकृती हो चुकी है एवं निविदा की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। साथ ही किसानों के कृषि कार्य पर सही समय पर सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति करने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा तालाबों से तालाबों को जोड़ने केनाल निर्माण हेतु अपने निधि से पर्याप्त राशि उपलब्ध करने की बात की है। दोनों ही कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे। नगर पंचायत भटगांव के परिसर द्वारा सर्वसम्मति से इन दोनों विषयों के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही नगर पंचायत के पार्षदों ने किसान संघ को उनके प्रयास के लिए आभार ज्ञापित किया ।

राष्ट्रीय सम्पादक गौरव रत्न सम्मान से सम्मानित हुए राजकुमार

बिलाईगढ़। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और निष्पक्ष लेखन के लिए राजकुमार जांगड़े को राष्ट्रीय संपादक संघ द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संपादक गौरव रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि से क्षेत्र के पत्रकारों, सामाजिक संगठनों एवं शुभचिंतकों में हर्ष का माहौल है। राष्ट्रीय संपादक संघ ने देशभर में पत्रकारिता के माध्यम से समाज हित में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तित्वों का चयन किया, जिसमें राजकुमार जांगड़े को उनके समर्पित, निष्पक्ष एवं जनसरोकारों से जुड़े पत्रकारिता कार्यों के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया।

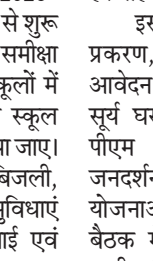

सम्मान की घोषणा होते ही बिलाईगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में उनके समर्थकों, सहयोगियों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाइयां एवं शुभकामनाएँ दीं। लोगों ने इसे क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि राजकुमार जांगड़े ने अपनी लेखनी के माध्यम से हमेशा समाज की आवाज़ को मजबूती से उठाया है।

इस अवसर पर राजकुमार जांगड़े ने राष्ट्रीय संपादक संघ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी निष्पक्ष, जनहितकारी एवं सकारात्मक पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेंगे। राजकुमार जांगड़े को मिले इस राष्ट्रीय सम्मान से क्षेत्र का नाम भी गौरवान्वित हुआ है तथा पत्रकारिता जगत में इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

पेज 9 के शेष

17 बॉटल नैनो...

संचालित मुन्ना कृषि सेवा केंद्र एवं देव कृषि केंद्र का निरीक्षण किया गया। विक्रय केन्द्रों द्वारा उर्वरक विक्रय की नियमित जानकारी प्रस्तुत न करने के कारण दोनों विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ग्राम दतान के वेद कृषि सेवा केंद्र तथा डबल लॉक पलारी का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। विकासखंड बलौदाबाजार के निरीक्षक लोकनाथ दिवान ने ग्राम सकरी के साहू ट्रेडर्स का निरीक्षण निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। उप संचालक कृषि दीपक नायक ने बताया कि जिला स्तर एवं अनुविभाग स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है जो जिले थोक एवं फुटकर विक्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण करेंगे तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

अनियंत्रित ट्रक दुकान ...

जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाई थी। बाई पास होने के बाद भी नगर के अन्दर से ट्रेलर ट्रक हाईवा जैसे भारी वाहन लगातार दौड़ रहे हैं। जिनके कहीं पर भी खड़े होने के कारण आए दिन गंभीर घटना प्रतिदिन घटते रहती है। दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण यह भी है कि स्थानीय व्यापारियों द्वारा सड़क के किनारे अतिक्रमण कर अपनी दुकानों के बोर्ड होर्डिंग शेड लगाए हैं, साथ ही दुकानों के सामने अवैध पार्किंग ठेला खोमचा लगने से स्वाभाविक रूप से लोगों की भीड़ हो जाती है। लेकिन न ही नगरपालिका और न ही यातायात विभाग को इसकी चिंता नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन किसी बड़ी दुघर्टना की प्रतीक्षा में खड़ी है। अब दुर्घटना के बाद नगरपालिका प्रशासन जागा है तथा आज मंगलवार को सड़क किनारे लगे होर्डिंग व ठेला खोमचा वालों को हटाने नोटिस थमाया। इससे पूर्व में भी इस तरह की कार्यवाही हो चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के दबाव में मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

महिलाओं के नाम...

परिवार अब महिलाओं के नाम पर जमीन और मकान पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और संपत्ति में अधिकार मजबूत हो रहा है। लाभार्थी नमिता साहू ने बताया कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीयन में मिलने वाली छूट से उनके परिवार को आर्थिक लाभ हुआ है। पहले रजिस्ट्री कराने में अधिक खर्च आता था, लेकिन अब खर्च कम होने से महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदना आसान हुआ है। इससे महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और कानूनी अधिकार भी मिल रहे हैं।

खंडहर में तब्दील हुआ ...

नजर आ रहा है। भवन की दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं, जगह-जगह प्लास्टर उखड़ गया है, खिड़कियां टूट चुकी हैं और परिसर में फैली अव्यवस्था छत पर मरम्मत का अभाव साफ संकेत दे रही है कि रखरखाव के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई।

अर्जुनी में अधिकारियों के ठहरने तक की व्यवस्था नहीं, फिर भी गहरी नींद में सोया संबंधित विभाग ग्रामीणों व क्षेत्र वासियों का कहना है कि यदि समय रहते इस भवन की मरम्मत और संरक्षण पर ध्यान दिया गया होता, तो आज यह अपनी पुरानी गरिमा के साथ विभिन्न सेवाओं के लिए अग्रणी होता।

अधिकारियों राजनैतिक गतिविधियों के लिए अलग से पैसे खर्च कर टेंट पंडाल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि लाखों की संपत्तियां धीरे-धीरे जर्जर होती जा रही हैं और जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदकर बैठे हैं। लोगों का कहना है कि गेस्ट हाउस केवल एक इमारत नहीं, बल्कि अर्जुनी अंचल की ऐतिहासिक पहचान और गौरव का प्रतीक और धरोहर भी है जिसे बचाना विभाग की जिम्मेदारी है।

वर्तमान हालात यह दर्शाते हैं कि पुरानी परिसंपत्तियों के संरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। यदि जल्द ही इस गेस्ट हाउस के जीर्णोद्धार, मरम्मत और पुनर्विकास की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में यह पूरी तरह खंडहर में बदल जाएगा। अब देखना यह है कि इससे जुड़े अधिकारियों को इसकी कितनी चिंता है, इस बदहाल व्यवस्था पर कब जागता है और इस ऐतिहासिक पहचान को बचाने के लिए आखिर क्या कार्रवाई करता है।

खबर संक्षेप

5वी-8वीं में मॉडर्न इंग्लिश स्कूल का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट

भाटापारा। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के पांचवी, आठवीं कक्षा बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट उत्कृष्ट एवं शत प्रतिशत रहा। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में आठवीं के बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान 98.17 प्रतिशत सोनाली माईती, द्वितीय स्थान 97.83

प्रतिशत, शुभम साहू और तृतीय स्थान 97 प्रतिशत मोहम्मद कैफ को मिला। कक्षा पांचवी में प्रथम स्थान 99 प्रतिशत दो विद्यार्थियों जीविका साहू और विद्या देवांगन को मिला। द्वितीय स्थान 98.5 प्रतिशत मनीष कुमार साहू और तृतीय स्थान 97 प्रतिशत अस्तित्व मिश्रा ने प्राप्त किया। प्राचार्या प्रीति ताम्हणे एवं स्टाफ ने बच्चों के प्रति उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं व्यक्त की।

कांग्रेस सनातन संस्कृति और संत समाज का लगातार अपमान कर रही

खरोरा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के एक बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए किसान मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रमेश शर्मा ने कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य और अन्य संतों के संबंध में दिया गया बयान बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है। कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति के चलते सनातन संस्कृति और संत

समाज का लगातार अपमान कर रही है। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र संतों और कथा वाचकों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। शर्मा ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि भगवान राम और सनातन संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस का नाता पहले भी विवादों में रहा है, यदि कांग्रेस आस्था और संस्कृति का सम्मान करती तो संत समाज के प्रति इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है। शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धर्मप्रेमी जनता संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के कुछ नेता राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयान दे रहे हैं ।

दिव्यांग रोजगार मेला 5 को

रायपुर। अस्थिबाधित, बौने, कम सुनने एवं देखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए 5 जून को रोजगार मेला सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार रायपुर में लगेगा। विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर के उपसंचालक रोजगार डॉ. शशी अतुलकर ने बताया कि यंग इंडिया के तत्वाधान में आयोजित इस रोजगार मेले में विभिन्न निजी प्रतिष्ठानों द्वारा दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

निधन

राजेंद्र कुमार

भाटापारा। मुंशी इस्माइल वार्ड

निवासी रमेश कुमार वर्मा के छोटे भाई राजेंद्र कुमार वर्मा का निधन हो गया। अंत्येष्टि हिन्दू श्मशान घाट रामसागरपारा में किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किए। एस आर मार्ट के संचालक राजकुमार एवं रवि के पिता थे।

स्कूल खुलने के पहले अधूरे निर्माण पूर्ण कराने व बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश

हरिभूमि न्यूज ▶▶| लवन

खबर का असर

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण कार्य एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने स्कूल खुलने से पहले समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को साफ नसीहत देते हुए कहा कि कही भी कोई भी गड़बड़ झाला की शिकायत नहीं आनी चाहिए, लवन तहसील के ग्राम पंचायत करदा हाई स्कूल पिछले साल से बंद होने पर नाराजगी जताई साथ ही अधिकारियों को जमकर फटकार लगाया है। व्यवस्था जल्दी दूरस्थ किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। करदा

टीएल बैठक में योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा

अब सांप-बिच्छुओं के साए में मिडिल स्कूल में शिफ्ट में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल

करोड़ों का हाई स्कूल भवन खंडहर में तब्दील

हरिभूमि न्यूज ▶▶| लवन

सरकार शिक्षा पर हर वर्ष लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर रही है लेकिन इसके बाद भी बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार नहीं हो पा रहा है। वहीं शासकीय विद्यालयों की अपेक्षा निजी विद्यालयों में बच्चों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। कई स्थानों पर भवन जर्जर होने के कारण छात्रों को दूसरे विद्यालयों में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रह रही है। तहसील के कई ऐसे स्कूल हैं, जहां छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा जाता है। कहीं बैठने के उचित व्यवस्था नहीं है तो कही सिर छुपाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूत छत नहीं है। कुछ ऐसा ही नजारा जिले के बलौदाबाजार ब्लॉक संकुल केन्द्र मरदा के ग्राम पंचायत करदा में संचालित हाई स्कूल में देखने को मिला जहां बच्चों के बैठने के लिए जमीन तो है पर सिर छुपाने के लिए मजबूत छत है और ना दीवारें। बच्चों के सिर पर हमेशा काल मंडराता रहता है। इस शासकीय हाई स्कूल को बने 10 वर्ष हो चुके हैं लगभग सात एकड़ जमीन बनी इस विद्यालय की भगवान ही मालिक है। ग्राम करदा के सरपंच इतवारा आत्माराम कंवर ने बताया कि 2014 में बनी इस विद्यालय में 2022 से 2024 मात्र 3 वर्ष ही स्कूल संचालित हो सकी है स्कूल की जर्जर स्थिति और छात्र-छात्राओं के भविष्य को देखते हुए पंचायत और शाला विकास समिति प्राचार्य समस्त पंचों द्वारा पंचनामा तैयार कर स्कूल बंद करके मिडिल स्कूल में दो पारियों में संचालित करने का फैसला लिया गया और जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी को जीर्णोद्धार लिखित आवेदन दिया। लेकिन आज तक शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दिया। सैकड़ों छात्र छात्राओं की भविष्य खतरे में आ रही है।

धंस गई फर्श, शौचालय टूटे और बोरवेल भी सूखा

गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में बने विद्यालय खेतों से घिरा हुआ है जहरीले जीव जंतुओं का होना स्वाभाविक है ऐसे में बच्चों का पढ़ना कितना जोखिम भरा हो सकता है वहीं स्कूल अंदर लगी फर्श टूट कर जमीन में धस गई है इसके अंदर सांप बिच्छू का होना स्वाभाविक है। टूटी फूटी शौचालय, बोर तो है पर पानी नहीं सबसे बड़ी समस्या तो यही है वहीं स्कूल परिसर की तत्कालीन कारण ना होना यह भी एक समस्या है। इस भवन की दीवारें पूरी तरह जर्जर हो चुकी है कभी भी होनी अनहोनी घटनाएं छात्र-छात्राओं के ऊपर घट सकती है। 15 जून से स्कूल संचालित होने वाले हैं और सबसे बरसात का मौसम भी है अभी तक उच्च अधिकारी तनिक भी इस ओर ध्यान नहीं दिए हैं अब देखना यह है कि शासन बच्चों के भविष्य के क्या करती है।

एसडीएम करेंगे औचक निरीक्षण

कलेक्टर ने शिक्षा सत्र 2026-27 अंतर्गत आगामी 15 जून से शुरू हो रहे स्कूलों में पढ़ाई की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन स्कूलों में निर्माण कार्य अधूरे हैं उसे स्कूल खुलने से पहले पूरा कर लिया जाए। सभी स्कूलों में पेयजल, बिजली, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं कार्यशील हो। रंगाई-पोताई एवं साफ़ -सफाई भी दुरुस्त हो। स्कूल खुलने पर शिक्षकों की उपस्थित अटेंडेंस एप्प में हो। एसडीएम स्कूलों का औचक निरीक्षण करें। उन्होंने शाला प्रवेश उत्सव की तैयारी के भी निर्देश दिये।कलेक्टर ने आगामी शैक्षणिक सत्र में बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने के लिये अभी से रणनीति तैयार करने कहा।

हाई स्कूल की समस्या को लेकर हरिभूमि में प्रकाशित खबर को संज्ञान लेते हुए टीएल बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों दो टूक शब्दों में कहा कि शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने जिन स्कूलों का रिजल्ट 50 प्रतिशत से कम है उन स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षक की समीक्षा बैठक लेने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर सभी स्कूलों में हर माह टेस्ट लिया जाए।कमजोर प्रदर्शन वाले बच्चों के लिये रिमेडियल क्लास की व्यवस्था हो। हर माह स्कूलों की प्रगति रिपोर्ट लें। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता, निशा नेताम मड़ावी सहित एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

मांग : व्यापारियों की समस्याओं के समाधान की उठाई मांग

जनदर्शन में कलेक्टर से मिले चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बलौदाबाजार

*चेंबर ने भूमि-भवन और पृथक थोक व्यापार क्षेत्र की मांग उठाई

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नगर इकाई के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष लक्ष्मी साहू के नेतृत्व में मंगलवार को जनदर्शन के दौरान कलेक्टर कुलदीप शर्मा से मुलाकात कर नगर के व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया तथा उनके निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा।

चेंबर पदाधिकारियों ने बताया कि हाल के दिनों में नगर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आगजनी की कई घटनाएं हुई हैं। फायर स्टेशन नगर से लगभग 12 किमी दूर होने तथा पानी की उपलब्धता में विलंब के कारण व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा बाजार क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे व्यापारियों में असुरक्षा का माहौल है। ज

ज्ञापन में व्यापारियों ने नगर के प्रमुख चौक-चौराहों एवं व्यस्त मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, रात्रिकालीन पुलिस गश्त बढ़ाने तथा मवेशी बाजार भैंसा पसरा, पुराना बस स्टैंड और रामसागर तालाब जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस चौकी अथवा अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था करने की मांग की। अध्यक्ष लक्ष्मी साहू ने कहा कि इन समस्याओं को लेकर पूर्व में भी जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि व्यापारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रशासन शीघ्र आवश्यक कदम उठाएगा। इस अवसर पर चेंबर के महामंत्री शिवप्रकाश तिवारी, उपाध्यक्ष उमेश अग्रवाल, पियूष मिश्रा, कोषाध्यक्ष लक्ष्मेंद्र अग्रवाल, मुख्य सलाहकार अभिषेक तिवारी तथा शिवम सतीश साहू सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

यातायात व्यवस्था सुधारने पर जोर

यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी चेंबर ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। पदाधिकारियों ने मवेशी बाजार परिसर को पार्किंग जोन के रूप में विकसित करने, सब्जी विक्रेताओं को निर्धारित शेडयुक्त चबूतरों में व्यवस्थित करने तथा मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाकर वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग रखी।

नगर में थोक व्यापार के लिए अलग स्थान विकसित करने का प्रस्ताव

चेंबर ने संगठन के संचालन एवं व्यापारियों तथा प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बाजार क्षेत्र के निकट भूमि एवं भवन उपलब्ध कराने की भी मांग की। साथ ही नगर में थोक व्यापार के लिए पृथक स्थान विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया।

जर्जर प्रधानमंत्री सड़क और खंडहर पंचायत भवन के खिलाफ सरपंच प्रतिनिधि ने खोला मोर्चा

हरिभूमि न्यूज ▶▶| सेल

ग्राम पंचायत सेल से साबर पहुंच मार्ग इन दिनों बेहद जर्जर स्थिति में है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत साबर के सरपंच प्रतिनिधि ओमप्रकाश वर्मा ने सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर मोर्चा खोलते हुए शीघ्र मरम्मत एवं पुनर्निर्माण की मांग की है।उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर सुशासन तिहार के दौरान ग्राम पंचायत डेराडीह में आयोजित कार्यक्रम में ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सड़क की हालत ऐसी हो गई है कि यह दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और गड्ढों में पानी भरने के बाद स्थिति और गंभीर हो जाएगी।

ओमप्रकाश वर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत साबर के करंजपारा मोहल्ले सहित कई स्थानों पर सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क किनारे की गिट्टियां बाहर निकलकर फैल गई हैं और डामर उखड़ने लगा है। उनका कहना है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और केवल लीपापोती का काम किया गया, जिसके कारण सड़क समय से पहले खराब हो गई।

पंचायत भवन भी बना चिंता का विषय

सरपंच प्रतिनिधि ने ग्राम पंचायत साबर के पंचायत भवन की जर्जर स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि पंचायत भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। भवन की जर्जर हालत को देखते हुए पंचायत का संचालन दूसरे भवन से किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन आज तक नए पंचायत भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत नहीं हुई है। उन्होंने शासन से शीघ्र नवीन पंचायत भवन निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की है।

मंत्री टंकराम ने विभागीय बैठकों और समस्याओं के निराकरण के लिए नियुक्त किए प्रतिनिधि

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बलौदाबाजार

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री एवं बलौदाबाजार विधायक टंकराम वर्मा ने विभागीय बैठकों में सहभागिता तथा जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है। इस संबंध में मंत्री कार्यालय से कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा को पृथक-पृथक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी तथा समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित

नियमित बैठकों में सहभागिता हेतु योगेश अग्रवाल को मंत्री प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बैठकों की सूचना मंत्री के साथ-साथ नियुक्त प्रतिनिधि को भी उपलब्ध कराई जाए। वही नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार से संबंधित नियमित बैठकों में भाग लेने तथा स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए श्रीमती नीलम सोनी को मंत्री प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उन्हें बैठक की सूचना मंत्री के साथ-साथ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से रख सकें। मंत्री कार्यालय द्वारा जारी दोनों आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्त प्रतिनिधि संबंधित विभागों की बैठकों में भाग लेकर क्षेत्र की समस्याओं, जन अपेक्षाओं एवं विकास कार्यों से जुड़े विषयों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा उनके निराकरण के लिए समन्वय स्थापित करेंगे। इन नियुक्तियों को प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर संवाद, विभागीय कार्यों की सतत निगरानी तथा जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

नशे की गिरफ्त में ग्रामीण, किशोरों में बढ़ती लत बनी चिंता का विषय

हरिभूमि न्यूज ▶▶| भैंसा

ग्रामीण अंचलों में तेजी से फैल रहे नशे का अवैध कारोबार अब सामाजिक बुराई से आगे बढ़कर कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। क्षेत्र में कम उम्र के किशोरों और युवाओं के नशे की चपेट में आने से अपराध की घटनाओं में भी वृद्धि की आशंका जताई जा रही है।

ग्रामीणों के अनुसार, 13 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे भी नशे की लत के शिकार हो रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों को शिक्षा और खेलकूद की ओर अग्रसर होना चाहिए, उस उम्र में वे नशे के संपर्क में आकर अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। सामाजिक जानकारों का मानना है कि नशे की लत के कारण कई युवा चोरी, मारपीट और अन्य आपराधिक

गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हाल ही में मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में तीन दिनों के भीतर दो युवाओं की हत्या की घटनाओं के बाद क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार के विस्तार से आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीणों ने नशे के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हुए बड़े स्तर पर अभियान चलाने की आवश्यकता बताई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध नशे के नेटवर्क पर अपेक्षित सख्ती नहीं दिखाई जा रही है। उनका कहना है कि केवल छोटे स्तर के आरोपियों पर कार्रवाई से समस्या का समाधान संभव नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

स्कूल और जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम

सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि नशे की समस्या से निपटने के लिए पुलिस-प्रशासन के साथ-साथ समाज, परिवार, जनप्रतिनिधियों और शिक्षण संस्थानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावकों को बच्चों की गतिविधियों और संगति पर ध्यान देने की जरूरत है, वहीं स्कूलों और ग्राम सभाओं के माध्यम से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। क्षेत्र के नागरिकों ने प्रशासन से नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण, युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में यह समस्या और गंभीर रूप धारण कर सकती है।

राज्य शासन ने दी 441.49 लाख की स्वीकृति

शहर में बनेगा हाइटेक 250 सीटर नालंदा परिसर

हरिभूमि न्यूज ▶▶| भाटापारा

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय द्वारा प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान के अंतर्गत भाटापारा को 250 सीटर नालंदा परिसर निर्माण कार्य के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है।

इस आदेश के तहत नगर पालिका परिषद भाटापारा को नालंदा परिसर के निर्माण के लिए विशेष रूप से 441.49 लाख की राशि अनुशंसित कर स्वीकृत की गई है।

छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1911 के नियमों के तहत जारी इस स्वीकृति से अब भाटापारा के छात्र-छात्राओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को पढ़ाई के लिए सर्वसुविधायुक्त, आधुनिक और शांत वातावरण वाला एक बड़ा केंद्र (नालंदा परिसर) अपने ही शहर में मिल सकेगा।

इसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने राज्य सरकार का आभार जताया और कहा भाटापारा के इतिहास में आज का दिन हमारे छात्र-छात्राओं और युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। शहर में एक सर्वसुविधायुक्त और आधुनिक लाइब्रेरी नालंदा परिसर की मांग लंबे समय से की जा रही थी। हमारे बच्चे उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों का रुख करते थे, जिससे उन पर और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ता था।

राज्य शासन द्वारा भाटापारा के लिए 441.49 लाख की इस भारी-भरकम राशि की स्वीकृति मिलने से अब हमारे शहर के भीतर ही 250 सीटों की क्षमता वाला भव्य 'नालंदा परिसर' बनकर तैयार होगा। यहां युवाओं को न केवल देश-दुनिया की बेहतरीन किताबें और ई-लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी, बल्कि पढ़ाई का एक शानदार माहौल भी मिलेगा।

सिंधु सेवा समिति ने वितरित किया शरबत और प्रसाद

हरिभूमि न्यूज ▶▶| भाटापारा

सिंधु सेवा समिति द्वारा सतगुरू साईं साधराम साहब की स्मृति में बब्बू होटल चौक, पुराना बस स्टैंड में शरबत व प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर इंदरलाल थारानी, डॉ. वासुदेव ठाकुर, श्रीचंद छाबड़िया, अजित थारानी, गोपी पारप्यानी, रितेश बालानी, ताराचंद किंगरानी, गुरमुख गंगवानी, सुरेश किंगरानी, तरूण सचदेव, कमल छाबड़िया, शिवम बालानी, सन्नी किंगरानी, मुकेश ग्वालानी, अनिल बालानी, महिला मंडल से सोनी छाबड़िया, शीतल आर्य, कंचन तलरेजा, रचना पारप्यानी, सुनीता गुरयानी, सुमन गोईंदानी, कोमल थदवानी, पूनम लेखवानी, रेखा माधवानी, मीना छाबड़िया, श्वेता अलरेजा, कर्णिका अलरेजा एवं कैलाश बालानी, राजेश छाबड़िया, नंदलाल तनवानी, महेश चंदानी, श्री मंगलानी, दिनेश सचदेव, विक्की छाबड़िया, राहुल गुरयानी, शंकर ठाकुर, विशाल बजाज, अन्नी थारानी, आकाश तनवानी उपस्थित थे।